विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा0 मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां । 29 मार्च, 1999 को भारतीय मानक समय के अनुसार उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में पूर्वाहन में 00.35 बजे रिक्टर स्केल पर 6.8 परिमाण का भूकम्प आया था । इस भूकम्प से छः जिले चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, उत्तर काशी और पौड़ी गढ़वाल प्रभावित हुए ।

(ग) तुलनात्मक दृष्टि से चमोली और रुद्रप्रयाग जिलो में भूकम्प का प्रभाव अधिक भीषण था । जी0 एस0 आई0 द्वारा गढ़वाल हिमालच में अब तक किए गए सवेंक्षण के अनुसार प्रदर्शित होता हैं कि बड़ी दरारों तथा निजी संरचनात्मक एलीमैंट्स के विफल होने, विभाजक दीवारों के ढ़ह जाने, जो विशेष रूप से गारा से बनी थी, के रूप में यह नुकसान चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिलो के 1800 वर्ग कि0 मी0 के क्षेत्र में हुआ हैं । फिर से बने कंकरीट की स्ट्रकर्म में मामूली नुकसान ही हुआ हैं । इस क्षेत्र में अनुमानित इनटैसिटी (सघनता) एम0 एस0 के0 स्केल पर VII रही हैं ।

चमोली सहित गहन अभिकेन्द्रित ट्रैक्ट में इसकी अधिमतम तीव्रता VIII नोट की गई । क्षेत्र में विभिन्न आइसोसीसमल जोन्स को कंसट्रेन (एकाकार) करने की दृष्टि से अध्ययन और सवेंक्षण जारी हैं ।

औबैदुल्लागंज, मध्य प्रदेश मे औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिये केन्द्रीय सहायता

2945. **श्री राघव जी :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के ओबैदुल्लागंज कस्बे में औषधीय एवं सुगंध पौध केन्द्र स्थित हैं,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त केन्द्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई हैं, और

(ग) उपरोक्त केन्द्र की प्रगति का ब्यौरा क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा0 मुरली मनोहर जोशी) : (क) मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा औषधीय तथासुगंधित पौधों के लिए एक पादप संसाधन केन्द्र की स्थापना ओबेदुल्लागंज, मध्य प्रदेश में की गई हैं ।

(ख) और (ग) बायोटेक्नोजॉजी विभाग ने बायोटेक्नोलॉजी अनुप्रयोग केन्द्र मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के लिए "ऊतक संवर्धन और क्लोनीय प्रवर्धन" के प्रयोग द्वारा स्थानिक एवं देशी वन पादप प्रजातियों के संरक्षण और बड़े पैमाने पर प्रवर्धन" शीर्षक के अंतर्गत एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को स्वीकृति दी हैं । इस परियोजना के अंतर्गत पादप संसाधन केन्द्र में कई पादप प्रजातियों के प्रोटोकॉल विकास और संरक्षण के लिए ऊतक संवर्धन अध्ययन किए जा रहे हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 45.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया हैं ।

एक दृढ़ीकरण सुविधा की स्थापना की गई हैं और इसका प्रयोग ऊतक संवर्धन के माध्यम से उगाये गये औषधीय और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों के दृढ़ीकरण के लिए किया जा रहा हैं । 150 से अधिक पादप प्रजातियों का संग्रहण किया गया हैं और संरक्षण केन्द्र में इनकी देख-रेख की जा रही हैं । 6 पादप प्रजातियों के लिए पुनरुत्पादन संबंधी अध्ययन शुरू किये गये हैं जिनमें दो औषधीय पादप-राउलफिया एस0 पी0 और एकोरस कैलेमस प्रजाति शामिल हैं ।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED AND UNSTARRED QUESTIONS SET FOR THE 15TH APRIL, 1999*

Growth,Target Under Ninth Plan-.

*341. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ninth Five Year Plan growth target has been cut to 6.5%.

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the areas in which the growth target has been mainly cut?

* The sitting of the Rajya Sabha on Thursday, the 15th April, 1999 was adjourned in view of the Motion of Confidence being discussed in the Lok Sabha, on 15th, 16th and 17th April, 1999. Answers to Questions put down in the lists for that day were raid on the Table of the House on Monday, the 19th April, 1999.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) Yes, Sir. The National Development Council (NDC), while approving the Approach Paper to the Ninth Five Year Plan (1997-2002) on January, 16, had approved a target growth rate of GDP of 7 per cent per year for the Ninth Plan. Taking into account the actual realisation of 5.0 per cent growth during 1997-98 (i.e., the first year of the Ninth Plan) as per the Quick Estimates and the expected realisation of 5.8 per cent during 1998-99 (i.e., the second year of the Plan) as per the Advance Estimate, the Planning Commission recommended to the NDC a reduction in the target rate of growth of GDP from 7 per*cent per year to 6.5 per cent per year average over the five years of the Ninth Plan. The NDC approved this revised target growth rate on 19 February, 1999. Implicit in this target is more than 7 per cent of average growth during the. remaining three years of the Plan.

(c) The sectoral implication of the change in the GDP growth rate from 7 per cent per year to 6.5 per cent per year in the Ninth Plan are:

(i) change in the growth rate of value-added in agriculture and allied sector from 4.5 per cent per year to 3.9 per cent per year, while retaining the growth rate of 4.5 per cent in the value of agricultural output.

(ii) change in the growth rate of manufacturing from 9.7 per cent per year to 8.2 per cent per year,

(iii) change in the growth rate Of electricity, gas & water supply from 10.6 per cent per year to 9.3 per cent per year.

(iv) change in the growth rate of construction from 5.7 per cent per year to 4.9 per cent per year,

(v) change in the growth rate of trade from 7.1 per cent per year to 6.7 per cent per year,

(vi) change in the growth rate of communications from 112.2 per cent per year to 9.5 per cent per year.

Central Assistance for Surat

*342. SHRI BANGARU LAXMAN:
SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the reasons for delay in releasing the Central assistance for the cyclone victims of Kandla and Jamnagar and flood affected areas in Surat;

(b) whether the Government are considering release of Central assistance in the near future; and

(c) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) It is primarily the responsibility of the State Government to undertake relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities from the allocation under Calamity relief Fund (CRF). An allocation of Rs. 154.83 crore was made to Gujarat during 1998-99 under CRF, which included Central share of Rs. 116.12 crore. The entire Central share was released to the State Government.

In addition to CRF, assistance is provided to the States from the National Fund for Calamity Relief (NFCR) for calamities of rare severity, after following the established procedure. Assistance from the NFCR is considered and ultimately approved by the National Calamity Relief Committee (NCRC) for release to the State.